छात्रों को लूटने का सरकारी अड्डा है हरियाणा शिक्षा बोर्ड

फ़रीदाबाद (म.मो.) रिश्वतखोरी व ग़रीब जनता को लूटने के लिये यूं तो हरियाणा का हर सरकारी दफ़्तर ही एक अड्डा है। इन अड्डों में भिवानी स्थित शिक्षा बोर्ड एक बड़ा अड्डा है। इस अड्डे की आपबीती सुनाई गांव फुलवाड़ी (पलवल) निवासी देवेन्द्र ने।

देवेन्द्र के परिवार के दो बच्चों-पल्लवी तथा कुलदीप ने 12 वीं की परीक्षा देने के लिये हरियाणा शिक्षा बोर्ड से ओपन स्कूल का फ़ार्म भरा था जो कि आजकल साइबर कैफ़े वालों के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाता है। आखिरी समय तक इन्तज़ार करने के बावजूद जब दोनों बच्चों का रोल नम्बर नहीं आया तो देवेन्द्र अपने चचेरे भाई को साथ लेकर बोर्ड के कार्यालय भिवानी पहुंचा। इस तरह के बहुत से लोग वहां रोज़ाना रोल नम्बर लेने या मार्क शीट लेने या रिज़ल्ट लेने को आये रहते हैं।

साईंस ग्रेजुएट देवेन्द्र जब सम्बन्धित बाबुओं के कमरे में पहुंचा तो वहां मौजूद चारों बाबू चाय नाश्ते में व्यस्त थे। गप्पे तो साथ में चलती ही हैं। कुछ देर देवेन्द्र को अनदेखा करने के पश्चात एक बाबू ने उससे पूछताछ की तो देवेन्द्र ने अपनी समस्या बताई। इस पर एक बाबू ने झुंझलाते हुए फ़ाइलें व काग़ज़ात इधर-उधर उलट-पुलट कर कुलदीप का रोल नम्बर तो दे दिया, परन्तु पल्लवी के बारे में कहा कि उसने दो बार फ़ार्म भर रखा है जिसका अर्थ यह निकलता है कि उसने हेराफ़ेरी करने यानी दो जगह से परीक्षा देने की योजना बनाई थी।

देवेन्द्र ने धर्मबीर नामक उस बाबू को समझाया कि कोई दो फ़ार्म नहीं भरे गये हैं। यदि दो फ़ार्म भरे होते तो दो फ़ीस भी तो बोर्ड के पास आई होती, जब बोर्ड के पास दाखिला फ़ीस ही एक आई है तो दो फ़ार्म कैसे भरे जा सकते हैं ? हां यह जरूर संभव है कि साइबर कैफ़े वाले ने ग़लती से दो बार पल्लवी का लिख दिया होगा जो कि कम्प्यूटर ने डिलीट दिखाया है।

यह बात तो बाबू भी समझता था, लेकिन सब ड्रामा तो वह केवल 500 रुपये ऐंठने के लिये कर रहा था, जो सारे वार्तालाप के बाद उसने खुल कर मांग भी लिये। देवेन्द्र रिश्वत देने वाला तो था नहीं, लिहाजा पहले वह सहायक सचिव के पास गया वहां बात नहीं बनी तो इस लूटेरा गिरोह के सरगना चेयरमैन जगबीर सिंह के दरवाजे पर पहुंचा। वहां बंदूक ताने एक पुलिसमैन बतौर सुरक्षा गार्ड खड़ा था। करीब 3 घंटे इन्तज़ार कराने के बाद लुटेरों के सरगना जगबीर ने उसे दफ़्तर में बुलाया जहां बोर्ड सचिव भी बैठा था।

देवेन्द्र से न कोई पुरानी जान-पहचान न देवेन्द्र ने अभी कुछ कहा कि लुटेरों का सरगना देवेन्द्र पर बरसने लगा। उसकी अनाप-शनाप धमकियां व गालियों का जब सारा जखीरा खत्म हो गया तो देवेन्द्र ने पूछा कि मैंने तो अभी अपनी बात रखी ही नहीं आप मुझ पर इतना क्यों बरस रहे हो ? मैं तो आपको यह बताने आया हूं कि आपका बाबू धर्मबीर रोल नम्बर देने के

लूटने की तैयारी : जगवीर सिंह, चेयरमैन हरियाणा शिक्षा बोर्ड

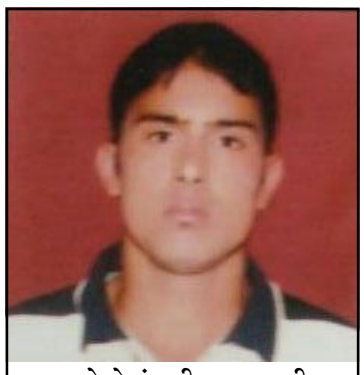

लुटने से इंकारी : फुलवाड़ी निवासी देवेन्द्र

500 रुपये मांग रहा है। इस पर तो वह लुटेरा सरगना और भड़क गया। उसे यह गंवारा नहीं था कि कोई ऐरा-गैरा उसके किसी कमाऊ पूत के बारे में शिकायत करने की गुस्तारवी करे।

नौटंकी करते हुए गिरोह सरगना जगबीर ने कहा कि 500 रुपये का नोट उससे ले जाओ और उसे दो तो वह उसे तुरंत विजिलेंस द्वारा रंगे हाथ पकड़वा देगा। बीच-बचाव की भूमिका निभाते हुए पास बैठे सचिव ने मामले को रफ़ा-दफ़ा करते हुए उस बाबू को बुलवा भेजा। देवेन्द्र को बाहर निकाल दिया। बाबू धर्मबीर अन्दर गया और 2-4 मिनट बाद मुस्कराता हुआ बाहर आकर देवेन्द्र से बोला ''बिगाड़ लिया मेरा कुछ ? जा अब पैसों से भी नहीं दूंगा रोल नम्बर।'

इसके बाद वह देवेन्द्र को भी जगबीर के सामने ले गया और आरोप लगाया कि ये लोग दो-दो बाद फ़ार्म भरकर बोर्ड के साथ धोखाधड़ी करते हैं और उल्टे हम पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। यह कहते हुए जगबीर ने पुलिस बुलाकर देवेन्द्र को गिरफ़्तार कराने तक की धमकी दे डाली। देवेन्द्र भी निडरता से डटा रहा और कहा कि बेशक बुला लो पुलिस, भेज दो जेल, जब उन्होंने कुछ ग़लत किया ही नहीं तो उसे काहे का डर ? इसके बाद उसे गनमैन द्वारा कमरे से बाहर करा दिया गया।

हताश व निराश होकर देवेन्द्र व उसका भाई बाहर आकर सीढियों पर बैठ गये। कुछ देर बाद उसी बाबू ने उन्हें फ़िर बुलाया और कहा कि तुम 200-200 बच्चों के रोल नम्बर ले जाते हो, तुमने यह धंधा बना रखा है। देवेन्द्र ने कहा कि उसने तो भिवानी ही पहली बार देखा है तो इतने लोगों के रोल नम्बर वह कैसे ले जा सकता है। खैर कुछ देर के झिकझिक के बाद शाम होते तक उसी बाबू ने रोल नम्बर भी दे दिया।

बाबू की बात पर ही ध्यान दिया जाय तो बात समझ में आती है कि उनके यहां से लोग 200-200 रोल नम्बर भी इकट्ठे लेकर जाते हैं। जाहिर है बोर्ड ने यह धंधा बना रखा है कि स्वत: कोई काम न करो, काम केवल तभी किया जाये जब कोई आकर चढावा देवे। वरना जरूरत क्या है किसी को बोर्ड मुख्यालय के चक्कर काटने की ? यह भी स्वत: सिद्ध है कि भ्रष्ट केवल बाबू नहीं है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो उनका सरगना है जिसे सरकार ने चेयरमैन का पद दे रखा है।

दरअसल भ्रष्टाचार मिटा चुकने का दावा करने वाली भाजपा की खटारा सरकार ने चेयरमैन जैसे तमाम पद बना ही लूट-खसूट के लिये रखे हैं इन पदों का मतलब ही यह होता है कि सरकार ने इन्हें लूट-खसूट का लाइसेंस दे दिया है।

खट्टर सरकार से संरक्षण की टीका लगवा कर बोर्ड दफ़्तर में चेयरमैन बने बैठे जगबीर सिंह को आरएसएस के हरियाणा सर्वेसर्वा पवन जिंदल के प्यादे के रूप में माना जाता है। जगबीर की सहायता में बैठा बोर्ड सचिव धीरेन्द्र खरकड़ा आईएएस अधिकारी है। इसके बाद, क्या देवेन्द्र जैसों के लिये कोई राह छोड़ी है 'ईमानदार' खट्टर सरकार ने ?

एसीपी चेची के तबादले पर प्रायोजित विरोध प्रदर्शन

पहले के तबादलों के वक्त कहां थे ये प्रदर्शनकारी ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) एसीपी क्राइम राजेश चेची का तबादला पिछले दिनों पंचकुला स्थित डीजीपी कार्यालय का कर दिया गया। इसे खुड्डा लाइन पोस्टिंग माना जाता है। उन पर आरोप था कि गत माह गांव फरीदपुर में हुई एक हत्या के आरोपी को अपराध स्थल पर जाकर उन्होंने मदद की थी।

सरकार द्वारा चेची के इस तबादले के विरोध में शनिवार 3 मार्च के दिन कुछ लोगों ने बीके चौक पर प्रदर्शन किया, बीके चौक से नीलम चौक तक का जुलूस निकाल कर सरकार से, चेची का तबादला रद्द करने की मांग की। यही नाटक 6 मार्च को सीपी दफ़्तर में दोहराया गया।

जानकार पूछ रहे हैं, करीब ढाई साल की तैनाती के दौरान चेची ने कौन से कद्दू में तीर मारे थे जो उनसे पहले किसी पुलिस अफ़सर ने नहीं मारे। अपराध के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई। अपराधियों को ढूंढ निकालने, पकड़ने व सज़ा कराने के जो रूटीन काम चेची ने किये वही काम इनसे पहले भी होते रहे हैं। हां यह सर्वविदित है कि उनकी यहां तैनाती मंत्री कृष्णपाल गूजर ने विशुद्ध जातीय आधार पर कराई थी ताकि मंत्री के जातीय गिरोह को पर्याप्त संरक्षण मिल सके, जो मिलता भी रहा।

चेची समर्थक प्रदर्शनकारी बतायें कि इससे पूर्व डीसीपी एनआईटी आस्था मोदी का तबादला हुआ तब वे कहां थे ? आस्था मोदी अब तक यहां रहे इस स्तर के अफ़सरों में सबसे बढिया मानी गयी हैं। चेची से पहले के क्राइम एसीपी राजेश फ़ोगाट में क्या कमी थी, उनका तबादला हुआ उस वक्त ये प्रदर्शनकारी क्यों कुछ नहीं बोले ? पूर्व पुलिस आयुक्त सुभाष यादव का तबादला हुआ तब ये प्रदर्शनकारी कहां सो रहे थे ? सारा शहर जानता है कि सुभाष यादव से मन्त्री कृष्णपाल गूजर काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि वे उनके जातीय गिरोह को खूब खींच कर लेते थे।

सुभाष यादव के समय ओल्ड फ़रीदाबाद थाने में मेवला महाराजपुर के गूजरों ने हुड़दंग मचाया था। तत्कालीन एसएचओ भारतेंदु से हाथापाई भी हो गयी थी, उसमें यादव द्वारा की गयी कड़ी कार्यवाही से बौखलाये मंत्री गूजर ने तत्कालीन एसएचओ व डीसीपी विजय प्रताप का तबादला कराया था, उस समय ये प्रदर्शनकारी कौन से बिल में छिपे थे ?

उसके बाद से ही मंत्री गूजर ने बड़े पैमाने पर फ़रीदाबाद में गूजर अफ़सरों की तैनाती करानी शुरू कर दी तथा उन्हें संरक्षित करने हेतु राज्य पुलिस प्रमुख (डीजीपी) के पद पर भी केपी सिंह गूजर को ही तैनात कराया। परन्तु सरकार को थोड़ी देर तो जरूर लगी परन्तु समझ में आ गया कि कृष्णपाल गूजर के इस गूजरवाद से पुलिस महकमे का भट्ठा बैठता जा रहा है। समझ आते ही सरकार ने चेची समेत उनकी पसंद के तमाम अफ़सरों को ठिकाने लगाना शुरू किया, जिससे आम जनता ने राहत की सांस ली है।

बहुत जल्दी हैरान हो गये निगमायुक्त, बने रहना है तो सब बर्दाश्त करना होगा!

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर की जनता नगर निगम के जिन लुटेरे अफ़सरों को बरसों से ढो रही है उनकी एक ही बानगी देख कर निगमायुक्त मोहम्मद शाइन हैरान व परेशान हो उठे। पूरे शहर में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें ये अफ़सर डकैती न मारते हों।

दिनांक 7 मार्च को निगमायुक्त ने नहर पार की भारत कॉलोनी में डाली जा रही सीवर लाइन का औचक निरीक्षण किया तो वे यह देखकर हैरान हो गये कि काम के नाम पर सारा फ़र्जीवाड़ा हो रहा था। इसी तरह 3 नम्बर में सीमेंट से बनने वाली एक सड़क को बनते देखा तो माल की क्वालिटी निहायत घटिया दर्जे की थी। इसके अलावा काम में अनियमिततायें भी बहुत की जा रही थीं जिन्हें देख कर निगमायुक्त हैरान हो गये।

सीवर लाइन का काम 9 करोड़ 61 लाख का तथा सड़क निर्माण का काम 10 करोड़ 96 लाख का है। निगमायुक्त महोदय ने दोनों कामों की पेमेंट रोकने के आदेश तो दे दिये लेकिन ठेकेदार अपनी पेमेंट का बड़ा हिस्सा तो पहले ही वसूल चुके।

सड़क वाला ठेकेदार करीब साढे सात करोड़ वसूल चुका है। पीछे सीवर वाला भी रहने वाला नहीं है।

निगमायुक्त ने तुरन्त, मौके पर एक एक्सियन, एसडीओ व जेई को तलब किया। उन्हें डांटा-धमकाया और कहा कि वे मौके पर मौजूद रह कर काम की निगरानी नहीं करते। उनकी इस लापरवाही को वे कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। उनसे इस बाबत स्पष्टीकरण भी मांगा।

अब सवाल यह पैदा होता है कि निगमायुक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? वे उनका बिगाड़ क्या सकते हैं ? निगमायुक्त और सह निगमायुक्त तो आते -जाते रहते हैं कैजुअल वर्कर की तरह; जबकि निगम के अधिकारी यहां पक्के तैनात हैं दामादों की तरह। इनका, आज तक न तो कोई कुछ बिगाड़ पाया है न बिगाड़ पायेगा क्योंकि इन्हें मोटा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

'मज़दूर मोर्चा' ने अनेकों बार आंकड़े प्रस्तुत करके बताया है कि किसी भी टेंडर का मात्र 40 प्रतिशत ही काम पर लगता है शेष 60 प्रतिशत राजनेताओं, अफ़सरों व ठेकेदारों में ही बंट जाता है। लूट के बंटवारे का यह सिलसिला ठीक उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन ठेकेदार के नाम पर टेंडर छुटता है। उसके बाद हर बिल पर तमाम लकड़बग्घे झपटते हैं और ठेकेदार को पेमेंट तभी हो पाती है जब सारे लकड़बग्घे तृप्त हो जायें।

हां, मोहम्मद शाइन इन तमाम लकड़बग्घों पर नकेल तभी कस सकते हैं जब चोरों की सरकार चाहेगी, वरना कई आयुक्त आये और गये।

रोजगार के आंकड़े से शर्मसार हुयी मोदी सरकार ने रोजगार के सरकारी आंकड़े बताने वाले सर्वे को ही बंद कर दिया

रोजगार के आंकड़े का आखिरी सर्वे सितंबर 2016 में जारी हुआ था जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई थी। इन्हीं आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था।

अब श्रम मंत्रालय ने फैसला लिया है कि वह इस सर्वे को नहीं कराएगा। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल रोजगार के सरकारी आंकड़े देश के सामने नहीं आएंगे। श्रम मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में लिखित जवाब में बताया गया है कि 2010 में जिस परंपरा की शुरुआत हुई है उसे 2016 में बंद कर दिया गया है।

गरीबी-रोजगार की स्थिति के बारे में सबसे प्रमाणिक सरकारी आंकड़ा मिलता है नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) से। इसी से अर्थव्यवस्था की स्थिति का जमीनी हिसाब मिलता है, और उसी के आधार पर आगे की सरकारी योजनाओं को बनाने की परंपरा रही है। यह सर्वे यह हर पांच साल में सरकार कराती है, जरूरत पड़ने पर कई बार बीच में भी हुआ है।

वर्ष 2016-2017 में एनएसएस का सर्वे होना था, जो नहीं कराया गया। चूंकि पिछला सर्वे 2011-12 में हुआ था, इसलिए 2016-17 में होना चाहिए था।

वजह साफ है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और वर्ष 2014 के बाद से गरीबी-बेरोजगारी में भीषण इजाफा हो रहा है, लिहाजा इस सर्वे की प्रक्रिया को ही सरकार ने शुरू नहीं किया।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06